मुक्त पाठ आधारित मूल्यांकन

2015-16

सामाजिक विज्ञान

कक्षा-IX

विषय	पृष्ठ
1. करें उन्नति साथ-साथ	1
2. भारत में खाद्य सुरक्षा	13

केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड

शिक्षा केन्द्र, 2, समुदाय केन्द्र, प्रीत विहार, दिल्ली-110301, भारत

मुक्त पाठ–आधारित मूल्यांकन

सामाजिक विज्ञान कक्षा–IX

1. विषय : करें उन्नति साथ–साथ

सार-संक्षेप

युगों से भारत दुधारु पशुओं और दूध वालों की भूमि रहा है। हमारा इतिहास लगभग 4000 वर्ष पूर्व से गाय और भैसों को घरों में पाले जाने का स्पष्ट उल्लेख करता है। डेयरी पशु पालन हड़प्पा के समय से हमारी संस्कृति और सभ्यता का अभिन्न अंग रहा है और आज भी है। वर्तमान में डेयरी पशु पालन–विशेषत: सहकारी संस्थाओं के माध्यम से, ग्रामीण क्षेत्रों के किसानों की आय को बढ़ाने, रोजगार के अवसर पैदा करने, युवाओं की प्रगति के लिए नये क्षेत्र निर्मित करने तथा खाद्य सुरक्षा को बनाए रखने में योगदान देने के साथ ही विकास और वृद्धि प्रदान करने का एक प्रभावशाली मंच बन चुका है।

इस पाठ का उद्देश्य विद्यार्थियों को इस योग्य बनाना है कि वे 'ऑपरेशन फ्लड' और भारत में श्वेत क्रान्ति के बारे में अपने ज्ञान में वृद्धि कर सकें; सहकारी समितियों विशेषत: भारत में डेयरी सहकारी समितियों की कार्यप्रणाली को समझ सकें; भारत में डेयरी उद्योग के उदय के कारणों का विश्लेषण कर सकें; डेयरी पालन और खाद्य सुरक्षा के बीच सम्बन्ध को समझ सकें; डेयरी उद्योग तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी के बीच सम्बन्ध स्थापित कर सकें; ग्रामीण और राष्ट्रीय आर्थिक विकास में डेयरी सहकारी समितियों की भूमिका का आंकलन कर सकें और सहकारिता, स्व-सहायता और लोकतन्त्र की अवधारणाओं को समझ सकें।

अ) भारत में सहकारी डेयरी संस्थाएँ

भारत में जिस प्रकार से आज डेयरी उद्योग का विकास हुआ है, वह अमूल के नाम से प्रसिद्ध 'कैरा जिला सहकारी दुग्ध उत्पादन संघ' आणद के बिना सम्भव नहीं था। इस दौरान 'ऑपरेशन फ्लड' के अन्तर्गत देश की सब सहकारी दुग्ध संस्थाओं ने भारत को विश्व में दूध का सबसे बड़ा उत्पादक देश बना दिया है। एक समय में दूध की कमी वाले देश का विश्व में सबसे बड़ा दूध उत्पादक बनना नि:सन्देह एक बड़ी उपलब्धि है।

कहानी का प्रारम्भ

1940 के दशक में ब्रिटिश भारत में डेयरी क्षेत्र में 'पॉलसन्स' नाम से प्रसिद्ध फर्म का प्रभुत्व था जिसकी स्थापना 1915 में श्री पेस्टोन जी एडुलजी ने बम्बई (वर्तमान में मुम्बई) में की थी। पॉलसन्स बोम्बे मिल्क स्कीम के अन्तर्गत शहर को तब दूध की आपूर्ति करते थे जब वह बम्बई प्रेसीडेन्सी का एक भाग था। गुजरात में कैरा जिला के किसान काफी मात्रा में दूध का उत्पादन करते थे और इस फर्म ने उनसे दूध लेने का निर्णय लिया। पॉलसन्स ने प्राइवेट ठेकेदारों को साथ लिया जो मध्यस्थ लोगों के रूप में वास्तव में कैरा गए और वहां के किसानों से कम दर पर दूध खरीदा। बम्बई में गुणात्मक दूध की नियमित आपूर्ति शुरू हुई जिससे पॉलसन्स और दूध के ठेकेदारों को बहुत लाभ हुआ। अब पॉलसन्स ने, जो पहले कॉफी उत्पादित करता था, क्रीम और मक्खन का उत्पादन भी शुरू कर दिया। इसने ब्रिटिश सरकार के सहयोग से डेयरी क्षेत्र में पूरा एकाधिकार जमा लिया था। किसान बाजार में किसी अन्य व्यापारी को दूध नहीं बेच सकते थे और उनको बलात्त केवल पॉलसन्स को दूध बेचने और वह भी कम दाम पर बेचने के लिए विवश किया गया। डेयरी के कार्य में कड़ी मेहनत और पशुओं के भोजन और चारे पर काफी खर्च करना पड़ता है- अत: किसान कम्पनी द्वारा दिए गए भुगतान से अप्रसन्न और असन्तुष्ट थे। इस व्यवस्था से कम्पनी और मध्यस्थों (दलाल) दोनों को लाभ हुआ परन्तु किसान खाली हाथ रहे।

इस अन्यायपूर्ण व्यापारिक व्यवहार से शोषित और पीड़ित किसान लोकप्रिय राष्ट्रवादी नेता सरदार बल्लभ भाई पटेल से मिले। बल्लभ भाई पटेल ने उन्हें एक होने तथा अपने संसाधनों पर अपना नियन्त्रण जमाने, दलालों से पीछा छुड़ा कर, पॉलसन्स को दूध की आपूर्ति रोकने तथा अपनी सहकारी समिति बनाने की सलाह दी तथा उत्पादन को एकत्र, संसाधित और वितरित करने के कार्य को अपने हाथ में लेकर पॉलसन्स और उसके ठेकेदारों को तगड़ा झटका देने को कहा। इस प्रकार कैरा जिला दुग्ध उत्पादक संघ, आणद का 1946 में जन्म हुआ (जो अब अमूल के नाम से प्रसिद्ध है) जिसमें केवल दो गांवों की सहकारी समितियां और मात्र 247 लीटर

दूध होता था। असामान्य क्रान्ति की इस चिंगारी को सुलगा दिया गया और दूध परिवर्तन का प्रतीक बन गया। संघर्ष के प्रारम्भिक दौर के बाद, किसानों के सहयोग और आपसी विश्वास से लाभ हुआ। उनकी सफलता की कहानी शीघ्र ही गुजरात के निकटवर्ती जिलों में फैल गई जहां अनेक सहकारी समितियां गठित की गईं।

तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री 'अमूल' की सफलता को देश के अन्य भागों में दोहराना चाहते थे। इसलिए 1965 में राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड का गठन किया गया और इसके चैयरमेन के रूप में डॉ० वर्गीस कूरियन ने 'ऑपरेशन फ्लड' के अन्तर्गत पूरे देश में दुग्ध क्रान्ति का नेतृत्व किया। इन डेयरी समितियों की सहायता के लिए तथा उनकी गतिविधियों को विस्तार देने के लिए देश के विभिन्न भागों में राज्य दुग्ध विपणन संघ गठित किए गए जिन्होंने राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के साथ मिलकर काम किया।

सोचिए और चर्चा कीजिए

दुग्ध क्रान्ति ने छोटे और हाशिये के किसानों की किस प्रकार सहायता की?

वर्तमान स्थिति

आज सहकारी दुग्ध समितियां देश में बिकने वाले संसाधित दूध का अधिकांश भाग बनाती हैं। आज भारत में 22 राज्य सहकारी दुग्ध विपणन महासंघ, 190 जिला दुग्ध संघ, 1,60,000 ग्राम डेयरी सहकारी समितियां और 1 करोड़ 50 लाख से अधिक दुग्ध उत्पादक हैं। वे सारे मिलकर दूध का उत्पादन, उसका संग्रहण, संसाधन तथा दूध और दूध के उत्पादनों को स्थानीय, राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय बाजारों में बेचते हैं।

गुजरात के आणद में स्थित राष्ट्रीय डेयरी महासंघ, डेयरी क्षेत्र की शीर्ष सहकारी संस्था है जो डेयरी क्षेत्र का नेतृत्व करती है। राज्यों एवं संघीय क्षेत्रों के सहकारी डेयरी संघ इससे सम्बद्ध हैं। इसका मुख्य उद्देश्य सहकारी डेयरी संस्थाओं की कार्यप्रणाली को समन्वय, नेटवर्किंग और प्रोत्साहन के माध्यम से सहायता प्रदान करना है। रक्षा बलों एवं अन्य अर्द्ध सैनिक संगठनों के साथ-साथ 'भारतीय रेल खान-पान एवं पर्यटन निगम' (आई.आर.सी.टी.सी) को अपनी सदस्य सहकारी संस्थाओं के माध्यम से दूध एवं दूध के उत्पादनों को बेचने में समन्वय स्थापित करना इसकी अति महत्वपूर्ण गतिविधियों में से एक हैं। यह राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के साथ मिलकर

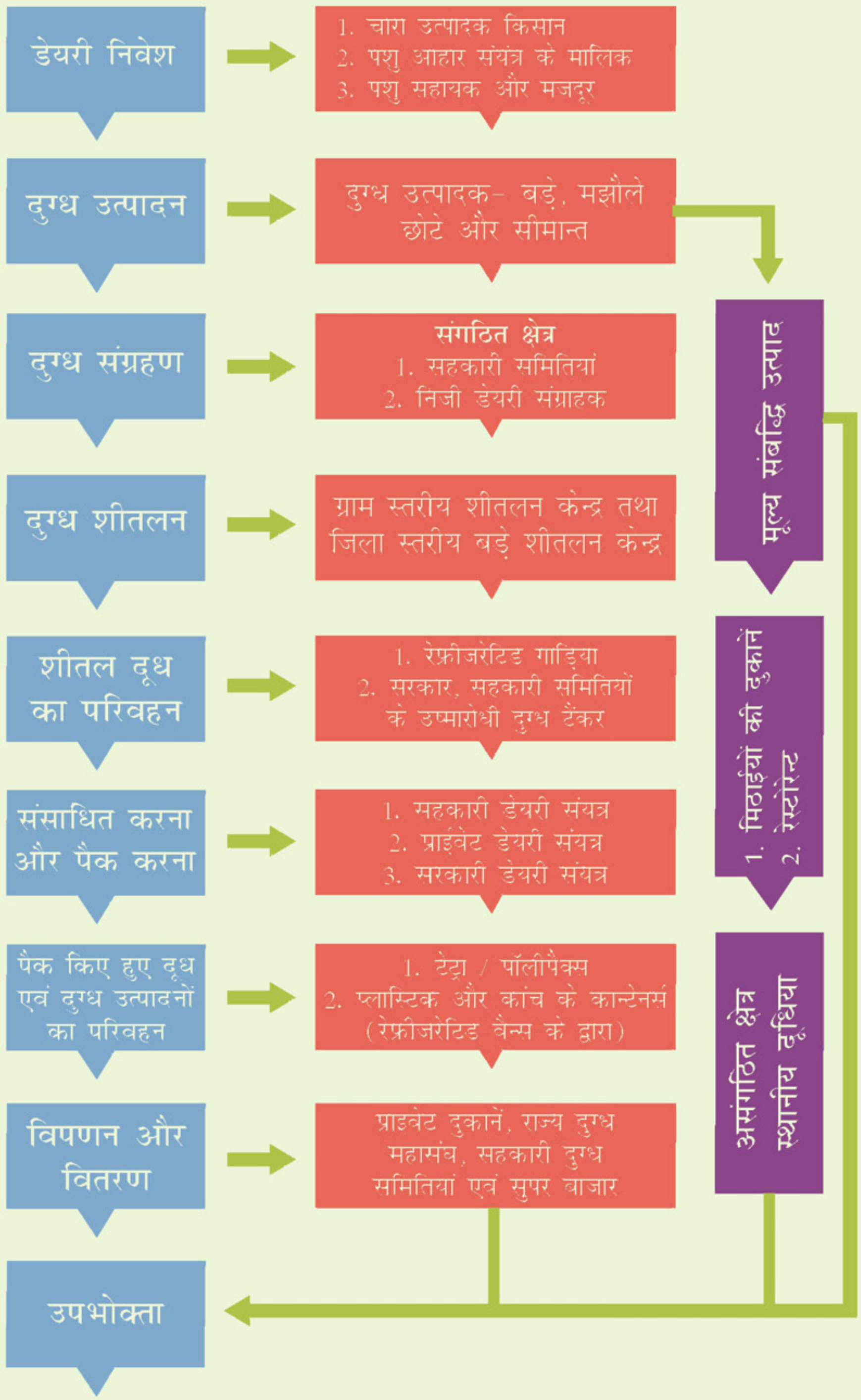

उसके सहयोग से काम करता है जो सहकारी डेयरी समितियों की प्रगति और विकास को बढ़ावा देने के लिए सहकारी डेयरी समितियों को वित्तीय सहायता, तकनीकी सहायता एवं किसानों तथा उनके पशुओं की भलाई और कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए चिकित्सकीय विशेषज्ञ उपलब्ध करवाता है।

सोचिये और चर्चा कीजिए

विज्ञान और प्रौद्योगिकी ने किस प्रकार दुग्ध क्रान्ति को एक वृहद् बढ़ावा दिया? विज्ञान की कौन-सी शाखा दूध के उत्पादन, संग्रहण और संसाधन से सीधे सम्बन्धित है? और कैसे?

इन वर्षों में सहकारी दुग्ध संस्थाओं ने गुणवत्ता, पैसे की कीमत और उपयोगिता देने में ख्याति अर्जित की है। अमूल (गुजरात), मदर डेयरी (दिल्ली), वीटा (हरियाणा), विजया (आन्ध्र प्रदेश), वेरका (पंजाब), नन्दिनी (कर्नाटक), मिलमा (केरल), गोकुल (कोल्हापुर) और एविन (तमिलनाडु) जैसे ब्रान्ड आज घरेलू नाम बन चुके हैं।

आज भारत विश्व में सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक होने के नाते विश्व के कुल उत्पादन के 18% का योगदान देता है। यह दूध, दूध का पाउडर, दही, क्रीम, मक्खन, घी, चीज (पनीर), लस्सी, आइसक्रीम जैसे डेयरी उत्पादनों का विश्व में सबसे बड़ा उपभोक्ता भी है।

क्या आप जानते हैं?

- ‘ऑपरेशन फ्लड’ को तीन चरणों में लागू किया गया था। पहला चरण 1979-80, दूसरा 1981-85, तीसरा 1985-96
- भारत 1999 में दूध का सबसे बड़ा उत्पादक देश बन गया और 2013-14 तक 137.6 मिलियन टन दूध के उत्पादन के साथ इस पद पर बना रहा।

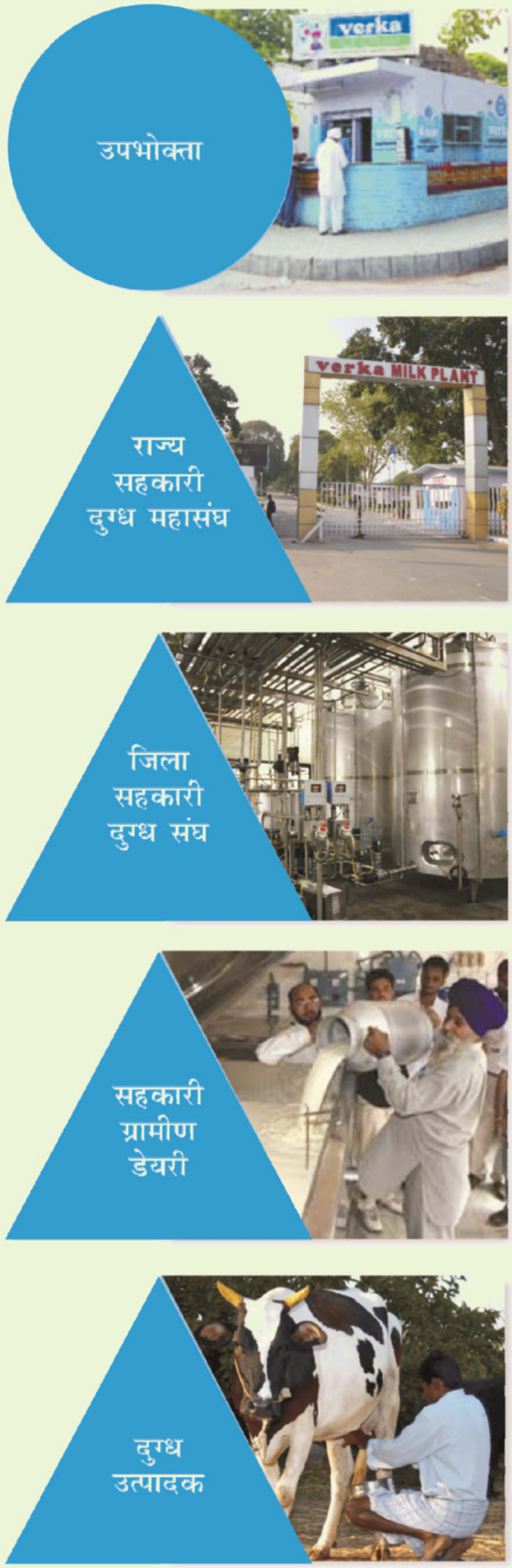

ब)   हरदीप सिंह और सुखजीत कौर की सफलता की कहानी

पंजाब के जिला गुरदासपुर की तहसील बटाला के एक छोटे से गांव धर्मकोट में हरदीप सिंह एक छोटे किसान के रूप में रहता था जिसके पास खेती के लिए भूमि का एक छोटा टुकड़ा और तीन गायें थीं जो उसके परिवार, जिसमें उसके बूढ़े माता-पिता, उसकी पत्नी तथा एक बेटा और एक बेटी शामिल थे, के लिए दूध देती थीं। एक छोटा किसान होने के नाते हरदीप सिंह का हाथ हमेशा तंग रहता था क्यों कि खेती का उत्पादन बहुत कम था और सूखे मौसम में तो कुछ पैदा नहीं होता था जिससे उसके कष्ट बढ़ जाते थे। ऐसे समय में परिवार को भूखा रहना पड़ता था या सिर्फ गाय के दूध पर ही, वह चाहे जितना भी हो, निर्भर रहना पड़ता था।

सामान्य दिनों में वह नजदीक के ढाबों तथा बस्ती के घरों में दूध बेचता था। इससे उसकी आय में वृद्धि तो होती थी परन्तु यह नियमित नहीं थी क्योंकि खरीददार कभी भी समय पर भुगतान नहीं करते थे और बाजार के भाव की तुलना में बहुत कम कीमत देते थे।

हरदीप सिंह ने कड़ा प्रयास किया लेकिन वह अकेले दम पर गुजारा नहीं कर सकता था। परिवार की ज़रूरतों को पूरा करने की चिन्ता उसे सताती थी क्योंकि उसके संसाधन बहुत कम थे। ऐसे समय में वह अपने मित्र गुरप्रीत सिंह से आर्थिक सहायता के लिए गया। गुरप्रीत सिंह गांव की सहकारी डेयरी समिति का सदस्य था और उसने हरदीप सिंह को यहां वहां से ऋण लेने के बजाय समिति में शामिल होने की सलाह दी। उसने कहा- "स्व-सहायता ही सबसे अच्छी सहायता है।" उसने उसे बताया कि कोई भी दूध उत्पादक डेयरी सहकारी समिति का न्यूनतम मूल्य पर एक शेयर खरीद कर तथा सम्बन्धित समिति को दूध बेचने की प्रतिबद्धता जता कर उसका सदस्य बन सकता है।

अपने दिमाग में अनके सन्देह होने के बावजूद हरदीप सिंह अपने मित्र की सहायता से अगले ही दिन समिति का सदस्य बन गया। वह समिति के दुग्ध संग्रहण केन्द्र पर बेचने के लिए कुछ लीटर दूध अपने साथ ले गया था जिसको प्रशीतित वैन के माध्यम से संसाधित होने के लिए जिला दुग्ध संघों को भेजा जाना था। दूध का परीक्षण किया गया और उसको हैरानी हुई कि दूध की गुणवत्ता के आधार पर उसे तुरन्त भुगतान कर दिया गया। कीमत भी ढाबों से प्राप्त होने वाली कीमत से लगभग दुगनी थी। हरदीप सिंह ने अपने मित्र का सही संदर्शन देने के लिए धन्यवाद किया और समिति को दूध बेचना शुरू कर दिया जो

दिन में दो बार संग्रहण करती थी। इससे उसको नियमित आय होने लगी जिससे वह अपने परिवार की ज़रूरतों को किसी न किसी तरह पूरा कर रहा था। अच्छे मौसम में सब कुछ ठीक चलता रहा परन्तु कमजोर मौसम में उसकी गायों को चारा नहीं मिल सका। वे कमजोर हो गईं और दूध की आपूर्ति कम हो गई।

उसने फिर गुरप्रीत सिंह से सम्पर्क किया। गुरप्रीत ने कहा- "हम शेयर होल्डर होने के नाते सहकारी समिति के स्वामियों में से एक हैं, जब हम दूसरे सदस्यों के साथ मिलकर इसकी प्रगति के लिए काम करते हैं तो बदले में हमारी भी प्रगति होती है। यह स्व-सहायता के माध्यम से आत्म-निर्भरता को प्राप्त करने के अतिरिक्त कुछ नहीं है।" हरदीप धीरे से बोला कि उसे कुछ समझ नहीं आया कि वह क्या कह रहा है।

गुरदीप ने समझाया कि गांव की डेयरी सहकारी समिति, जिला और राज्य सहकारी समिति से सम्बद्ध है जो दूध को संग्रहित, संसाधित और बेचती है। "उसके द्वारा अर्जित लाभ को हम सबके साथ सांझा किया जाता है जिसको दूध को संसाधित करने और पशु आहार संयत्र लगाने, अन्य आवश्यक सामान को खरीदने तथा सदस्यों को डेयरी के नवीनतम तरीकों को प्रयोग करने के लिए प्रशिक्षित करने हेतु निवेशित किया जाता है। इस लिए जिला सहकारी समिति अपने सदस्यों को कमजोर मौसम में फैक्ट्री निर्मित पशु आहार प्रदान करती है तथा गर्भाधान एवं उन्हें स्वस्थ रखने हेतु आवश्यक सहायता भी देती है। इतना ही नहीं यह अपने सदस्यों को नाम मात्र की ब्याजदर पर अपने उद्यम को विस्तार देने एवं सुरक्षित रखने हेतु ऋण देती हैं। आपको भी इस सुविधा का लाभ उठाना चाहिए।" उसने कहा।

"क्या मैं अपने घर पर डेयरी की गतिविधियां चला सकती हूँ और डेयरी सहकारी समिति का सदस्य बन सकती हूँ " सुखजीत कौर ने पूछा। गुरप्रीत ने उत्तर देते हुए कहा- "क्यों नहीं? वास्तव में कई महिलाएं डेयरी सहकारी समितियों की सफल सदस्य हैं और बढ़िया काम कर रही हैं। इस प्रकार से आप अपने परिवार की आय बढ़ाने में बराबर की भागीदार बनने के लिए सशक्त हो सकेंगी और आर्थिक रूप से स्वतंत्र होने पर अच्छा महसूस करेंगी। इससे हरप्रीत को भी परिवार के लिए अतिरिक्त समय देकर कृषि पर ध्यान केन्द्रित करके अधिक आय कमाने का अवसर मिल सकेगा।"

इससे पति-पत्नी दोनों की समझ बढ़ी और उन्होंने अपने मित्र की सलाह का अनुसरण किया। आज 15 वर्षों के बाद हरदीप सिंह और सुखजीत कौर पांच हेक्टेयर भूमि के संयुक्त स्वामी हैं जहां हरदीप बहुविध

कृषि प्रणाली और आधुनिक वैज्ञानिक तरीकों के प्रयोग से मिश्रित खेती करता है, वहीं सुखजीत 45 गायों के साथ डेयरी चलाती है तथा दुग्ध सहकारी समिति में उसके अच्छे शेयर हैं। उनके बेटे ने डेयरी प्रबन्धन में स्नातक की उपाधि प्राप्त की है। वह अपनी मां की सहायता करता है और साथ ही पंजाब राज्य दुग्ध सहकारी फेडेरेशन के स्वामित्व में चल रहे वेरका दुग्ध संसाधन संयंत्र में नौकरी करता है। उनकी बेटी ने जीव-प्रौद्योगिकी का अध्ययन किया है और पशु पालन के क्षेत्र में काम कर रही है। परिवार का आर्थिक स्तर और क्रय शक्ति कई गुणा बढ़ गई है। भुखमरी के दिन अब गए समय की बात है। अब वे खाद्य के मामले में सुरक्षित हैं। उन्होंने अपने संसाधन निर्मित किए हैं और अब आत्म निर्भर हैं।

- ☆ दम्पत्ति द्वारा गुरप्रीत की सलाह का अनुपालन करने के निर्णय तथा परिवार के खुशहाल होने के बीच सम्बन्ध को खोजने का प्रयास कीजिए। स्थानीय स्तर पर सहयोग और संयुक्त प्रयास ने किस प्रकार उन्हें वर्तमान स्थिति प्राप्त करने में सहायता की होगी।
- ☆ जैसा हरदीप के मामले में हुआ- वैसा हमेशा नहीं होता। डेयरी सहकारी समिति के सदस्यों के सामने अनेक समस्याएं हो सकती हैं। इन समस्याओं को खोजने और विश्लेषित करने के कोशिश कीजिए। उन्हें हल करने का व्यवहारिक समाधान भी सुझाइये।

स) महिलाओं के समूह डेयरी पालन में भुगतान को सुनिश्चित करते हैं।

"मुझे अपने पहले वाले दूध क्रेता से 22,000 रुपये की राशि वापिस प्राप्त करनी है। दो वर्ष के बाद भी वह इसको देने के लिए तैयार नहीं हैं। हर बार जब मैं अपनी राशि के लिए जाती हूँ तो वह कोई न कोई बहाना बना लेता है और कई बार तो अपनी दुकान पर ही नहीं होता।।" तिरुवेंकोइलपट्टी गांव की सुश्री चेल्लम ने यह बात कही जो तमिलनाडु के जिला पुडुकोटी के तालुक इलुपुर से सम्बन्ध रखती है।

उसकी तरह भिन्न-भिन्न गांवों के अन्य अनेक ऐसे लोग हैं जिसके पास ऐसी ही कहानियाँ हैं- स्थानीय दुग्ध विक्रेताओं अथवा चाय की दुकानों को बेचे गए दूध के लिए अदायगी का शेष होना। लेकिन आज एम.एस. स्वामीनाथन अनुसंधान फाउंडेशन द्वारा पुडुकोटी में ग्रामीण महिला उद्यमी महासंघ के उद्घाटन के

बाद सुश्री चेल्लम अपना बकाया वसूल पाने के प्रति आश्वस्त हो सकती है क्योंकि उसकी सहायता के लिए एक समूह है।

यह समूह 2012 में 450 महिला सदस्यों की प्रारम्भिक सदस्यता के साथ गांव में इस सर्वेक्षण के बाद शुरू हुआ था कि उस गांव में डेयरी पशु पालन अनियमित मासिक अदायगी, दूध के त्रुटिपूर्ण विश्लेषण, पशु स्वास्थ्य और प्रबन्धन की कम जानकारी के कारण एक गैर कृषि कार्य के रुप में अधिक लोकप्रिय नहीं था। सदस्यों के निवेदन के आधार पर कोमथा दुग्ध उत्पादक संघ के नाम से एक महासंघ बनाया गया जिसमें ग्रामीण महिला उद्यमी महासंघ द्वारा प्रबन्धित 375 महिला डेयरी उद्यमी शामिल थीं। इसका उद्देश्य पशु खरीदने के लिए ऋण तक पहुंच की एकीकृत व्यवस्था को बढ़ावा देना, सस्ते चारे के बैंक बनाना, कृमि खाद की इकाइयां लगाना, गौ-मूत्र से जैविक उत्पाद विनिर्मित करना, पशु स्वास्थ्य को बनाए रखना और बीमा को प्रोत्साहित करना था।

पारदर्शी प्रबन्ध व्यवस्था को सुनिश्चित करने के लिए कोमथा दुग्ध उत्पादक संघ द्वारा नौ सदस्यों की एक कमेटी निर्वाचित की गई जो प्रति मास अपने दूध के व्यवसाय से सम्बन्धित समस्याओं पर चर्चा करती है। आज तक इस संघ ने 6 दुग्ध संग्रहण केन्द्र स्थापित किए हैं और अपने सदस्यों को दुधारु पशु खरीदने के लिए चक्रीय ऋण देने हेतु 13 लाख रुपये प्रदान किए हैं।

इस समूह के निरन्तर प्रयास से विलम्बित अदायगी के मुद्दे को हल कर लिया गया है और दूध की आपूर्ति आरम्भिक 100 लीटर से बढ़कर 12,000 लीटर प्रति मास हो गई है जिसकी वार्षिक सकल आय 25 लाख रुपये है। ग्रामीण महिला उद्यमी महासंघ की दीर्घकालिक रणनीति 2015 के अन्त तक दूध उत्पादकों की संख्या को 1000 तक बढ़ाना है।

स्त्रोत : द हिन्दू, 30 अप्रैल 2014

क्या आप जानते हैं?

राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार 2013-14 के दौरान देश में सर्व महिला डेयरी सहकारी समितियों की संख्या 26700 तक बढ़ चुकी है। मार्च 2014 में पूरे देश में डेयरी सहकारी समितियों की महिला सदस्यों की संख्या 4.38 मिलियन हो चुकी है।

सोचिए और चर्चा कीजिए

- ☆ बड़ी संख्या में महिलाओं द्वारा डेयरी के क्षेत्र में प्रवेश करने के कारण।
- ☆ महिला सशक्तीकरण, खाद्य सुरक्षा और राष्ट्र निर्माण के बीच सम्बन्ध।
- ☆ महिलाओं को बड़े स्तर पर सशक्तीकरण और उत्थान की ओर ले जाने वाले अन्य क्षेत्र।
- ☆ ग्रामीण क्षेत्रों में सर्व महिला डेयरी सहकारी समितियों का योगदान।

दी गई सामग्री के आधार पर भारत में डेयरी उद्योग का स्वोट (SWOT) विश्लेषण कीजिए।

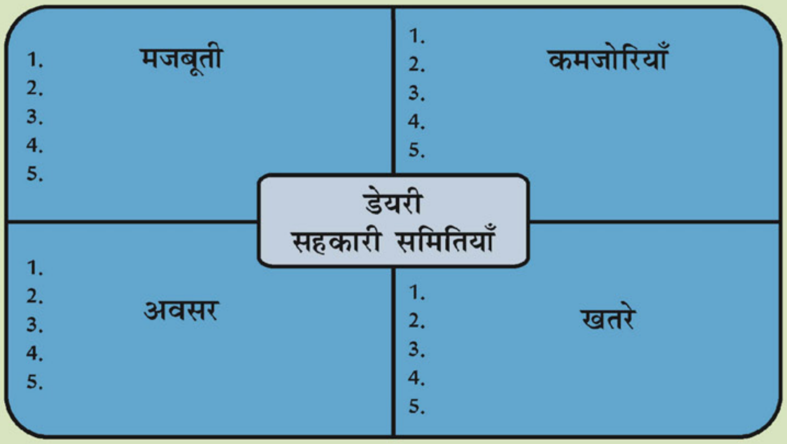

सहकारी समितियां डेयरी कार्यों के अतिरिक्त अन्य क्षेत्रों जैसे कृषि, मछली पालन, उद्योग, आवास, विपणन और वित्त इत्यादि में काम कर रही हैं। अनाज की सहकारी समितियां, चीनी सहकारी समितियां, फल और सब्जी सहकारी समितियां और कपड़ा सहकारी समितियां कुछ उदाहरण हैं। वे केवल ग्रामीण क्षेत्रों के सामाजिक-आर्थिक उत्थान में ही योगदान नहीं देती अपितु शहरी क्षेत्रों में भी बहुत सक्रिय हैं।

करने और चर्चा के लिए विषय

कम से कम चार अलग-अलग क्षेत्रों में सहकारी समितियों के बारे में अधिक जानने की कोशिश कीजिए और उनके काम करने के आधारभूत सिद्धान्तों को जानिए।

यह भी दर्शाने की कोशिश कीजिए कि वे देश में खाद्य सुरक्षा प्रदान करने में किस प्रकार सहायता करती हैं।

संदर्भ

- ✰ Agricultural Cooperatives: Key to Feeding the World, Dr. Narayan G. Hegde, BAIF Development Research Foundation, Pune
- ✰ Milkfed Punjab, Citizens Charter
- ✰ National Dairy Development Board, Annual Report 2013-14

Websites

- ✰ www.nddb.org
- ✰ http://www.amul.com
- ✰ www.thehindu.com
- ✰ http://www.dairyfarming.co.in
- ✰ http://www.indiadairy.com
- ✰ http://www.vitaindia.com

नमूना प्रश्न और अंक योजना सहित उनके प्रस्तावित उत्तर

1. दुग्ध सहकारी समितियां किस प्रकार राष्ट्र निर्माण में योगदान करती हैं? स्पष्ट कीजिए। 5 अंक

उत्तर : दुग्ध सहकारी समितियां राष्ट्र निर्माण की दिशा में निम्नलिखित ढंग से योगदान करती हैं–

क) लोगों को स्वालम्बी बनाने और उद्यमिता को प्रोत्साहित करने के द्वारा

ख) ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में रोजगार प्रदान करके

ग) खाद्य सुरक्षा और स्वास्थ्य प्रदान करके

घ) अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देकर

ङ) विज्ञान और प्रौद्योगिकी के प्रयोग को बढ़ावा देकर

च) राष्ट्र की अर्थव्यवस्था में योगदान देकर

2. सहकारी समितियों की कोई पांच कमियां उजागर कीजिए। 5 अंक

उत्तर : सहकारी समितियों की कमियां–

क) अपर्याप्त पूंजी

ख) अक्षम प्रबन्धन

ग) सदस्यों के बीच एकता और समन्वय की कमी

घ) आकार की सीमाएं

ङ) अपर्याप्त प्रेरणा

च) निर्णय निर्माण और निर्णय क्रियान्वयन में देरी

छ) सरकारी हस्तक्षेप

मुक्त पाठ–आधारित मूल्यांकन

सामाजिक विज्ञान कक्षा–IX

2. विषय : भारत में खाद्य सुरक्षा

सार-संक्षेप

1996 के विश्व खाद्य शिखर सम्मेलन ने खाद्य सुरक्षा को ऐसी स्थिति के रूप में परिभाषित किया जब सभी लोगों के स्वस्थ और सक्रिय जीवन के लिए पर्याप्त, सुरक्षित और पौष्टिक भोजन तक हर समय पहुंच हो। खाद्य सुरक्षा की अवधारणा प्राथमिक रूप से भोजन की उपलब्धता (देश में खाद्य उत्पादन), भोजन तक सबकी पहुंच (सबके लिए भोजन तक पहुंच) और भोजन के लिए सामर्थ्य (भोजन खरीदने की क्षमता) से सम्बन्धित है जो लोगों के आहार की आवश्यकताओं को पूरा कर सके। यह अध्ययन एक विद्यार्थी के परिप्रेक्ष्य में 1947 में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से खाद्य सुरक्षा को अधिक सुनिश्चित बनाने के भारत के प्रयासों को समझने की एक कोशिश है।

इस पाठ के उद्देश्य है विद्यार्थियों को इस योग्य बनाना कि खाद्य सुरक्षा का अर्थ और सिद्धान्त समझ सकें; भारत में कृषि सुधारों को समझ सकें; भारतीय कृषि के विकास में भूमि सुधारों और हरित क्रान्ति की भूमिका समझ सकें; खाद्य आत्म निर्भरता के अर्थ और प्रभाव को समझ सकें तथा कृषि नीति और भारत के स्वतंत्रोत्तर काल में इसके क्रियान्वयन का मूल्यांकन कर सकें।

भारत में खाद्य सुरक्षा

नौवीं कक्षा की विद्यार्थी, शिक्षा, 1943 के बंगाल के महा–अकाल के अध्याय में भारत के औपनिवेशिक काल के बारे में पढ़ रही थी जिसमें अनुमानतः 30 लाख से अधिक लोग मारे गए थे। उसने इस विषय पर अपने पिता से पूछने का फैसला किया जो किसी विदेश के विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हैं।

- भूख और कुपोषण से मर रहे लाखों भारतीयों पर ध्यान न देने जैसा कुकृत्य अंग्रेज हमारे साथ कैसे कर सकते थे?
- क्या स्वतंत्रता के बाद भारत का ऐसी किसी आपदा से सामना हुआ है?
- क्या हम ऐसी स्थिति, के अब घट जाने पर, उससे निपटने के लिए तैयार हैं?

उसने अपने पिता को ये प्रश्न मेल कर दिए और अपने विद्यालय चली गई। सारा दिन वह इस विषय पर सोचती रही और अपने सहपाठियों को उनके टिफिन बॉक्स से बचा हुआ बाकी भोजन कूड़ेदान में डालते हुए देखती रही। (कई बार उसने स्वयं भी ऐसा किया है)। यकायक उसको महसूस हुआ कि शादियों में कितना भोजन बेकार जाता है। क्या हम भोजन व्यर्थ गवां कर अपराध नहीं कर रहे? घर पहुँचने के बाद उसने दोपहर का भोजन छोड़कर लैपटॉप उठा लिया और अपने पिता द्वारा भेजी गई मेल को पढ़ने लगी। मेल को देखते समय उसके चेहरे पर मुस्कान थी, जिसमें लिखा था-

प्रिय शिक्षा,

तुम्हारी मेल ने मुझे आश्चर्यचकित कर दिया कि तुम कैसे इतनी जल्दी बड़ी हो गई कि स्वतंत्रता से पहले और बाद के खाद्य सुरक्षा जैसे जटिल मामले पर आलोचनात्मक चिन्तन कर रही हो! निश्चय ही तुम्हारा यह कहना ठीक है कि अंग्रेजों और उनकी पार्लियामेन्ट की भूमिका भारतीय परिप्रेक्ष्य से ही नहीं अपितु मानवीय परिप्रेक्ष्य से भी विचलित करने वाली है। तथापि मैं तुम्हारे अन्तिम प्रश्न के विषय में सोच रहा था कि वर्तमान भारत में खाद्य सुरक्षा के मुद्दे पर स्थिति कितनी चिन्ता जनक है। मैं इस बात पर केन्द्रित रहूंगा कि स्वतंत्र भारत की क्या उपलब्धि है बजाय इसके कि मैं अतीत पर अपनी छाती पीटता रहूं जब हमारा राजनीतिक अथवा आर्थिक नीति बनाने और निर्णय लेने पर कोई नियंत्रण नहीं था। हमें वर्तमान समय में खाद्य सुरक्षा की वर्तमान स्थिति को समझने के लिए अपनी यात्रा 1947 से शुरु करनी चाहिए।

भारत में ब्रिटिश शासन के अन्तर्गत भारत अधिकांशतः उपेक्षित और यथावत रहा। इस कारण भारत की स्वतंत्रता के बाद उसे ठीक करने के लिए तत्काल सुधारों की ज़रूरत थी।

भारतीय कृषि के सामने की समस्याएं

सांस्थानिक समस्याएं	तकनीकी समस्याएं	सामान्य समस्याएं
1. त्रुटिपूर्ण किराएदारी की समस्या 2. ऋण की कम सुविधाएं 3. अपर्याप्त विपणन सुविधा 4. भू-स्वामित्व का आकार	1. उत्पादन की पुरानी तकनीकें 2. सिंचाई सुविधाओं की कमी 3. कृषि शैली	1. सामाजिक वातावरण 2. भूमि पर जनसंख्या का दबाव 3. भूमि निम्नीकरण 4. आजीविका कृषि 5. फसल सम्बन्धी हानियां

इन समस्याओं से निपटने के लिए सरकार ने इन वर्षों में अनेक सुधार शुरू किए। जैसे-

1. भूमि सुधार (सांस्थानिक सुधार)
2. हरित क्रान्ति (तकनीकी सुधार)
3. सामान्य सुधार

☆ **भूमि सुधार (सांस्थानिक सुधार)** - स्वतंत्रता के बाद भू-स्वामित्व, कार्यकाल और किराएदारी व्यवस्था से उपजी बाधाओं को दूर करने की दृष्टि से भूमि सुधार लागू किए गए। इन सुधारों में मध्यस्थों को समाप्त करना (जमींदारों, महलवारों इत्यादि को) किरायेदारी सुधार (किराए का नियमन, अवधि की सुरक्षा, किराएदारों के लिए स्वामित्व अधिकार), भूमि की सीमा तय करना, भूमि चकबन्दी, सहकारी कृषि इत्यादि शामिल हैं। अमीर और शक्तिशाली भू-स्वामियों द्वारा कानून की कमियों और छिद्रों के दुरुपयोग के कारण भारत में ऐसे भूमि-सुधार अधिक सफल नहीं हुए।

☆ **हरित क्रान्ति (तकनीकी सुधार)** - प्रथम पंचवर्षीय योजना का प्राथमिक लक्ष्य कृषि क्षेत्र के विकास को प्राथमिकता देना था। भूख के कारण किसी भी भारतीय की मृत्यु न होने देने को सुनिश्चित करने के लिए वह आवश्यक था और बहुत हद तक हम इसमें सफल रहे। दूसरी और तीसरी पंचवर्षीय योजना में कृषि क्षेत्र के मशीनीकरण और प्रौद्योगिकी को अद्यतन करने पर पर्याप्त सरकारी निवेश किया गया, जो विशेष रूप से पूरे देश में सिंचाई सुविधाओं पर खर्च किया गया था, यद्यपि हमने लगातार दो खराब फसलों (1965-67) का सामना किया था।

सूखे के दुष्प्रभाव तथा धीमे कृषि उत्पादन पर विजय पाने के लिए नई रणनीति 'हरित क्रान्ति' बनाई गई। इस नई नीति पैकेज में निम्नलिखित को कम कीमत पर उपलब्ध करवाना शामिल था-

क) अधिक उत्पादन देने वाले बीजों के प्रकार

ख) रसायन आधारित उर्वरक (जिन्हें प्राय: एन.पी.के. के नाम से जाना जाता है जिसका अर्थ है नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटाशियम) के साथ कीटनाशक।

ग) पर्याप्त जल आपूर्ति और किसानों के लिए ऊर्जा के व्यापारिक स्रोत।

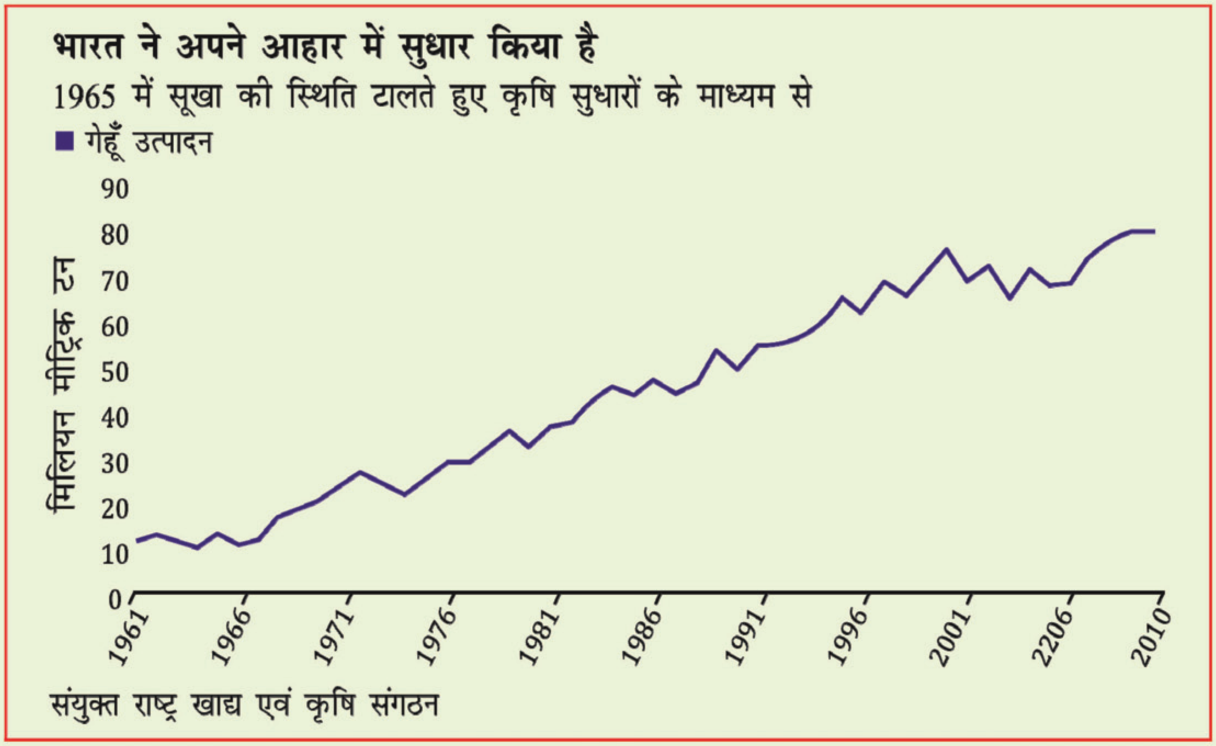

स्रोत : संयुक्त राष्ट्र का खाद्य एवं कृषि संगठन

इस नई कृषि रणनीति जिसे 'बीज, उर्वरक, पानी' भी कहा गया है, को 'मूल्य समर्थन नीति' और सब्सिडी (सब्सिडी सरकार द्वारा दिया गया आर्थिक लाभ होता है) के साथ जोड़ा गया जिसने हमारे देश की खाद्य आवश्यकताओं को पूरा करने और खाद्य आवश्यकताओं की दिशा में आत्म-निर्भरता की ओर बढ़ने का परिणाम दिया। मैक्सिकन वैज्ञानिक प्रो० नॉर्मन बरलॉग के नेतृत्व में विकसित अधिक फसल देने वाले (HYU) बीजों ने खाद्य की कमी वाले देश को अतिरिक्त खाद्य सम्पन्न देश में बदल दिया। हरित क्रान्ति के परिणामों को निम्नलिखित आंकड़ों से प्रस्तुत किया जा सकता है।

खाद्य उत्पादन में वृद्धि दर्शाती तालिका (सभी आंकड़ें मिलियन टन में)

क्रम संख्या	उत्पादन	1965-66	2011-12
1.	गेहूँ	11.1	93.9
2.	चावल	35.1	92.8
3.	मोटा अनाज	26.1	32.5

स्त्रोत : आर्थिक सर्वेक्षण 2012-13

उपरोक्त तालिका गेहूँ, चावल और मोटे अनाज के लक्षित क्षेत्रों में शानदार वृद्धि को दर्शाती है। बाद में इसी प्रकार की वृद्धि दालों और तिलहनों में भी दर्ज की गई जिसने देश में इनकी पर्याप्त उपलब्धता को सुनिश्चित किया। तदापि हरित क्रान्ति के बारे में आलोचना के कुछ तार्किक बिन्दु रहे हैं जिनकी अवहेलना नहीं की जानी चाहिए। जैसे-

क) इसको केवल पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और आन्ध्र प्रदेश जैसे राज्यों तक सीमित रखा गया। इससे बाद के वर्षों में देश में क्षेत्रीय असंतुलन बढ़ गया।

ख) हरित क्रान्ति के परिणाम स्वरूप अधिकांश अमीर और समृद्ध किसानों को लाभ का बड़ा हिस्सा मिला और गरीब किसान क्रान्ति के लाभ से वंचित रहे।

ग) रसायनिक उर्वरकों, कीटनाशकों, रोगनाशकों इत्यादि के कारण अधिक मशीनीकरण से पारिस्थितिकी निम्नीकरण अधिक हुआ।

11वीं पंचवर्षीय योजना रिपोर्ट के अनुसार सकल घरेलू उत्पादन में कृषि के वर्तमान 2% योगदान के स्तर को बढ़ा कर 4% तक ले जाने के लिए तुरन्त एक दूसरी हरित क्रान्ति की आवश्यकता है।

☆ **सामान्य सुधार** - कुछ अन्य सामान्य सुधार जैसे सिंचाई सुविधाएं, ऋण सुविधाएं, विपणन सुविधाएं और सबसे बढ़कर मूल्य समर्थन नीति भी सरकार द्वारा प्रदान की गई।

प्रिय शिक्षा, अब तक तुम यह समझ गई होगी कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से हम कितनी यात्रा और प्रगति कर चुके हैं। तदापि आप को समकालीन परिस्थितियों पर भी ध्यान देना चाहिए। हमारे देश की दुविधा यह है कि एक तरफ हम प्राथमिक रूप से कृषि प्रधान देश हैं तो दूसरी ओर हमारे पास

कालाहांडी और काशीपुर (उड़ीसा), पलामू (झारखण्ड), बारान (राजस्थान) जैसे कुछ अन्य क्षेत्र हैं जहां से पिछले वर्षों में यदा-कदा भुखमरी के समाचार आते रहे हैं। यद्यपि स्वतंत्रता के बाद बंगाल जैसे महा अकाल की कोई घटना नहीं हुई है।

मुझे आशा है कि तुम खाद्य सुरक्षा की आधारभूत अवधारणा को समझती हो जिसमें तीन पक्ष शामिल होते हैं-

क) उपलब्धता (देश में खाद्य उत्पादन)

ख) पहुंच (भोजन का सबकी पहुंच में होना)

ग) सामर्थ्य (भोजन खरीदने की क्षमता)

सैद्धान्तिक और ऐतिहासिक आधार पर भारत की बफर स्टॉक नीति एक बीमा उपागम का कार्य करती है (गेहूँ, चावल और मोटे अनाज का सरकार द्वारा भारतीय खाद्य निगम के माध्यम से किया गया स्टॉक बफर स्टॉक होता है) यह बफर स्टॉक कम उत्पादन के समय में कमी के विरुद्ध एक बीमा के रूप में रखा गया स्टॉक होता है। खाद्य नीति का विकास और इस प्रकार स्वतंत्र भारत में बफर स्टॉक का निर्माण आपदा उन्मुख नीति की कहानी है जिसे न्यायोचित विकास प्रदान करने के साधन में परिवर्तित किया जा रहा है।

परन्तु हमें इस निष्कर्ष पर नहीं पहुँचना चाहिए कि सरकार द्वारा अब तक उठाए गए कदमों से भारतीय खाद्य वितरण व्यवस्था में सब कुछ ठीक-ठाक हैं। भारतीय खाद्य निगम द्वारा संग्रहित खाद्य अनाज को कम कीमत की दुकानों (उचित दर की दुकानों) के माध्यम से वितरित किया जाता है जिसे सार्वजनिक वितरण प्रणाली कहते हैं। प्रारम्भ में यह प्रणाली सार्वभौमिक थी जो अमीर और गरीब के बीच बिना किसी भेदभाव के लागू थी। परन्तु 1992 के साथ ही इसमें परिवर्तनों की एक श्रृंखला देखी जा सकती है।

- ☆ 1992 में नवीनीकृत सार्वजनिक वितरण प्रणाली (देश के दूरस्थ और पिछडे 1700 ब्लॉकों के लिए)।
- ☆ लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (देश के सभी भागों में गरीबों की सेवा के लिए) : जून 1997 से सरकार द्वारा गरीब और गैर-गरीब के लिए अलग-अलग कीमत की नीति को पहली बार अपनाया गया।

- ☆ दिसम्बर 2000 के बाद से अन्त्योदय अन्न योजना (निर्धनता रेखा से नीचे वाले निर्धन 1 करोड़ परिवारों को लक्ष्य बना कर) और 'अन्नपूर्णा योजना' (गरीब वरिष्ठ नागरिकों का लक्ष्य लेकर) शुरू की गईं।

पिछले ही दिनों सरकार ने खाद्य (भोजन) के अधिकार का अधिनियम 2013 पारित किया है जिसका लक्ष्य भारत में सात करोड़ से अधिक लोगों को कम दर पर खाद्य अनाज (खाद्यान्न) प्रदान करना है। इस अधिनियम के मुख्य प्रावधानों के अन्तर्गत लाभ प्राप्त करने वाला प्रत्येक व्यक्ति प्रति मास 5 किलो अनाज निम्नलिखित दरों पर पाने के लिए प्राधिकृत है :

चावल	3 रुपये / किलो
गेहूँ	2 रुपये / किलो
मोटा अनाज	1 रुपये / किलो

सरकार ने कीमतों को स्थिर रखने और कम कीमत पर भोजन उपलब्ध करवाने के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली का प्रयोग करके आम आदमी के खाद्य सुरक्षा के सार भाव को सुनिश्चित किया है। ऐसे सभी लाभों के बावजूद सार्वजनिक वितरण प्रणाली को भ्रष्टाचार, खराब गुणवत्ता और खाद्य आपूर्ति के मामले में आलोचना का सामना करना पड़ा है। अनाज से भरे गोदामों और खाद्य आपूर्ति के गलने सड़ने के बावजूद आज भी भूख से मरने की घटनाएं घटती हैं।

मुझे आशा है कि अब तक तुम अच्छी तरह आश्वस्त हो चुकी होगी कि वर्तमान भारतीय अर्थव्यवस्था में 1943 के बंगाल महा-अकाल जैसी कोई घटना नहीं घट सकती। तदापि हमें प्राकृतिक संसाधनों और वित्तीय संसाधनों का उपयोग करते समय व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए।

प्रेम सहित, मुझे तुम्हारे उत्तर 'तुमने क्या सीखा' की प्रतीक्षा रहेगी।

पापा

सन्दर्भ

- ☆ www.who.in
- ☆ Economic Survey (2012–13).
- ☆ Five Year Plan documents.

नमूना प्रश्न और अंक योजना सहित उनके प्रस्तावित उत्तर

1. भारत में हरित क्रान्ति के परिणामों का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। 5 अंक

प्रस्तावित उत्तर

1) कुछ फसलों तक सीमित

2) भूमि सुधारों की अवहेलना

3) क्षेत्रीय असंतुलनों में वृद्धि

4) बेरोजगारी में वृद्धि

5) पारिस्थितिकी का निम्नीकरण

6) विद्यार्थियों द्वारा अन्य कोई सही उत्तर

2. विश्व में खाद्य उपलब्धता के सम्बन्ध में निम्नलिखित चित्र पर टिप्पणी कीजिए। 5 अंक

प्रस्तावित उत्तर

वर्षों से विश्व बढ़ती हुई जनसंख्या के साथ खाद्य संसाधनों की कमी का अधिक से अधिक सामना कर रहा है। आने वाले समय में इससे भुखमरी की सम्भावनाएं बढ़ जाएंगी।

विद्यार्थी द्वारा की गई कोई अन्य उचित व्याख्या। **5 अंक**

केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड

शिक्षा केन्द्र, 2, समुदाय केन्द्र, प्रीत विहार, दिल्ली–110301, भारत

फोन: 011-22509256-59 • वेबसाइट: www.cbse.nic.in